

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना का मूल्यांकन

(आईईडीसी)

उत्तर प्रदेश

जनक वर्मा

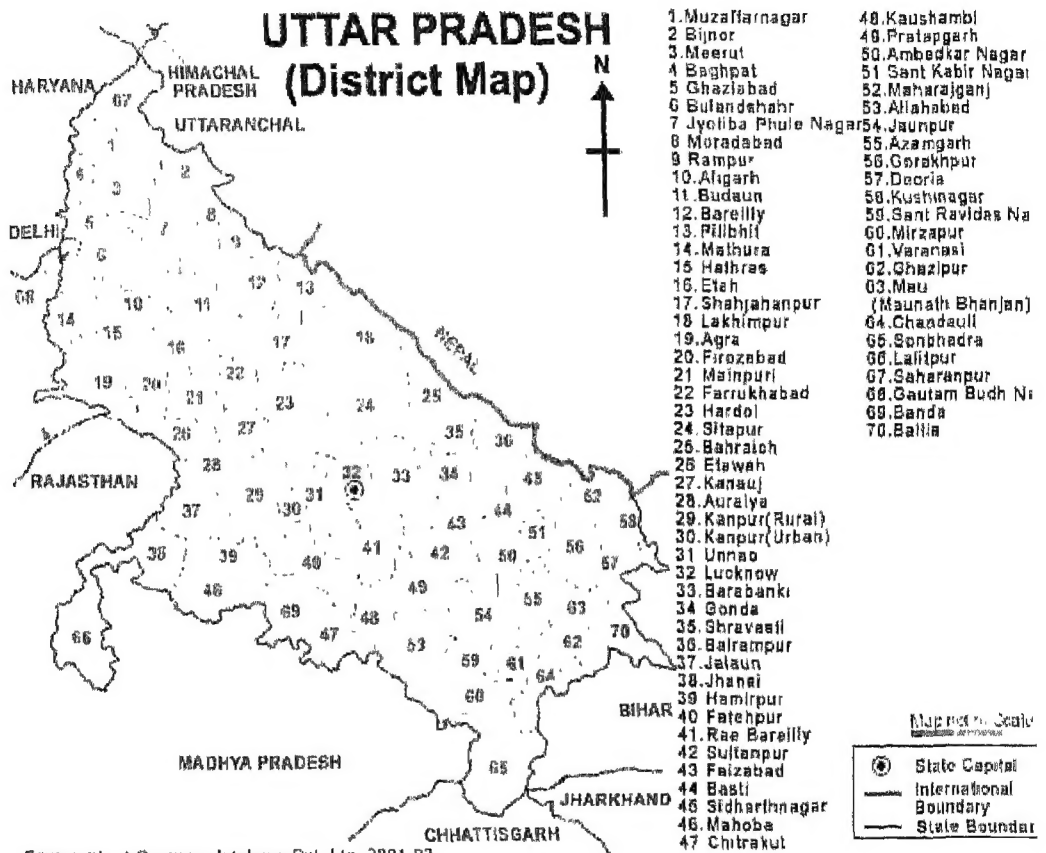
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

विषय सूची:

उत्तर प्रदेश में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के मूल्यांकन की एक व्याख्या	1
प्रदेश में समेकित शिक्षा योजना की अद्यतन स्थिति	3
आई.ई.डी.सी. के मूल्यांकन का एक अध्ययन	5
विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना से आच्छादित विद्यालयों की सूची प्राथमिक स्तर	7
उच्च प्राथमिक स्तर	8
आई.ई.डी.सी. जनशाला में (यू.पी.)	21
जनशाला कार्यक्रम के उद्देश्य	22
विकासखण्डवार विकलांगता विवरण जिला-लखनऊ	23
विकलांग बच्चों हेतु किए गए प्रयास	24
विभिन्न विभागों/संस्थाओं से समन्वय	25
विकलांग बालकों से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन	26

Contents

➤ Acknowledgement	(i)
➤ Map of Uttar Pradesh	(ii)
➤ Integrated Education for the Disabled (IED) in District Primary Education Plan (DPEP), (U.P.)	11
➤ Objectives	12
➤ Coverage	12
➤ Assessment of Children with disabilities	14
➤ Distribution of aids and appliances	15
➤ Capacity Building and Manpower Development	17
➤ Material Development	18
➤ Initiatives taken by DPEP in U.P	19
➤ Annexure	30
▪ Questionnaire for teachers to study the impact of IEDC	



Acknowledgement

Nodal officer from the State for Data Collection:

Sh. K.N. Awasthi,
Deputy Director,
Directorate of Basic Education,
Lucknow, UP.

Field Investigators:

Sh. S.P. Pandey,
SCERT,
UP, Lucknow

Sh. Nilesh Anand,
UP, Lucknow

Assistance provided by JPF:

Sh. M.M. Joice

Computer Assistance & Analysis of Data:

Sh. Ravindra Patel

Head, DEGSN, NCERT:

Prof. Neerja Shukla

Janak Verma
Principal Investigator
& Reader, DEGSN
NCERT.

उत्तर प्रदेश में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के मूल्यांकन की एक व्याख्या:

उत्तर प्रदेश में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना, शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में वर्ष 1987-88 से प्रारंभ की गयी थी। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के 15 जनपदों के एक-एक प्राथमिक विद्यालयों और इन्हीं जनपदों में से 10 जनपदों के एक-एक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की गयी थी। जिन जनपदों में समेकित शिक्षा योजना संचालित की गयी उनकी सूची संलग्न है।

योजना का प्रबंधन

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के संचालन का दायित्व शिक्षा निदेशालय उ.प्र. इलाहाबाद को दिया गया था। प्रारंभ में इस कार्य के लिए कोई अलग से प्रबंधन तंत्र या प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था, बल्कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में अधिकारी और सहायक, योजना के संचालन के कार्य को देखते रहे। वर्ष 1997 में एक प्रकोष्ठ का गठन अवश्य किया गया परन्तु केवल एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को 5000.00 संकलित मानदेय पर मात्र एक वर्ष के लिए रखा गया और आदेश में यह भी आवंटित किया, कि यह प्रकोष्ठ अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं के अनुश्रवण के दायित्व का भी वहन करेगा। कालान्तर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान एवं परामर्श विभाग को इस योजना के संचालन का दायित्व सौंपा गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एवं प्रचारित विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना की गाईड लाईन में, प्रस्तावित प्रशासनिक प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया। प्रभावी अनुश्रवण एवं प्रबंधन के अभाव में इस योजना हेतु

भारत सरकार से केवल तीन वर्षों 88-89 और 89-90 और 90-91 तक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिसका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है। वर्ष 91-92 से अब तक यह योजना लगभग सुषुप्त अवस्था में रही।

प्राप्त वित्तीय सहायता

क्रम	वर्ष	धन
1	1988-89	9,55,400.00
2	1989-90	12,16,400.00
3	1990-91	16,97,680.00
योग		38,69,480.00

आई.ई.डी.सी. के मूल्यांकन के चलते प्राप्त धनराशि के उपभोग का विवरण जनपदों से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। 8 जनपदों से सूचना प्राप्त भी हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार जिन मदों में धन का उपयोग किया गया वे मर्दे निम्नलिखित हैं:

1. संदर्भ कक्षा का निर्माण (केवल एक कमरे का निर्माण)
2. विकलांग बच्चों को यूनीफार्म की आपूर्ति
3. विकलांग बच्चों को पुस्तकों की आपूर्ति
4. विकलांग बच्चों को मार्ग व्यय के भत्ते का भुगतान
5. उपकरणों का क्रय।

चूँकि प्रकोष्ठ का गठन औपचारिक रूप से नहीं किया गया और विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक एवं समन्वयक नहीं नियुक्त किए गये, विकलांग बच्चों की आवश्यकतानुसार संदर्भ कक्षा क्रियाशील न हो सके और न ही विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा योजना की संकल्पना के अनुसार

अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया और न ही इन बच्चों के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकार की शिक्षण सामग्री विकसित की गयी। संबंधित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा अपनी सूझ-बूझ से उपलब्ध संसाधनों, से सामान्य बच्चों के साथ इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पढ़ाने का कार्य किया गया।

1 प्रदेश में समेकित शिक्षा योजना की अद्यतन स्थिति:

प्रदेश के चार जनपदों इलाहाबाद, सहारनपुर, उधमसिंह-नगर और गोरखपुर सम्मिलित रूप से इन चार जनपदों के 52 ब्लकों के सभी प्राथमिक विद्यालयों को समेकित शिक्षा योजना से पूर्ण रूप से आच्छादित करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। योजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही इन चारों जनपदों में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

2 प्रशासनिक प्रकोष्ठ का गठन:

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और संचालित करने के लिए, गाईड लाईन के प्रावधान के अनुसार प्रशासनिक प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रकोष्ठ को क्रियाशील किया जायेगा और समेकित शिक्षा योजना को गाईड लाईन में उल्लिखित, विधि एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश में इस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने का प्रयास किया जायेगा।

3 विकलांग बच्चों के प्रति जागरूकता:

उल्लेखनीय है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति सर्व संबंधित में जागरूकता एवं विकलांग बच्चों की पहचान का कार्य संपूर्ण प्रदेश के समस्त जनपदों में करने का कार्यक्रम बनाया गया है। जुलाई से प्रारम्भ होने वाले "विद्यालय चलो अभियान" के पखवारे में अन्य कार्यक्रमों के साथ पूरे प्रदेश में विकलांग बच्चों की पहचान का कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें विकलांग बच्चों की पहचान, उनकी विकलतांगता का विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रमाणीकरण और देय सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही साथ यथासंभव विकलांग बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था सभी विद्यालयों में समेकित शिक्षा की संकल्पना के अनुसार करने का प्रयास किया जायेगा।

4 स्वायत्तसेवी संगठनों को प्रोत्साहन:

इस योजना को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू करने के लिए स्वायत्त सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति समेकित शिक्षा योजना को संचालित करने वाली इच्छुक संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन कर वित्तीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजने के दायित्व के वहन करने के साथ-साथ, प्रदेश में समेकित शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने का भी प्रयास करती है। इस समिति द्वारा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अन्य आवश्यक विभाग जैसे - समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, हरिजन समाज कल्याण, विकलांग समाज कल्याण एवं पुनर्वास विभागों से समन्वय और सहयोग, प्राप्त होना सुगम हो गया है।

5 आई.ई.डी.सी. के मूल्यांकन का एक अध्ययन:

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रारंभ किए गये एक मूल्यांकन अध्ययन में विभिन्न जनपदों से आंकड़े एकत्र करने का कार्य मार्च/अप्रैल 2000 से प्रारम्भ हो गया था।

तीन जनपदों : (1) लखनऊ (2) इलाहाबाद (3) सुलतानपुर से विकलांग बच्चों अभिभावकों और अध्यापकों के साक्षात्कार प्रपत्र भरवाकर प्राप्त भी हो गये हैं। जिनका विवरण जनपदवार निम्नलिखित के अनुसार है :

क्रम सं.	जनपद का नाम	अध्यापक साक्षात्कार प्रपत्रों की संख्या	अभिभावकों के साक्षात्कार	विकलांग बच्चों के साक्षात्कार प्रपत्रों की संख्या
1.	लखनऊ	7	1	2
2.	इलाहाबाद	2	-	-
3.	सुलतानपुर	4	-	-
कुल		13	1	2

टिप्पणी: प्रदेश में समेकित शिक्षा योजना हेतु 1992 के बाद कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी। अतः योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चे 8 साल की अवधि बीत जाने के बाद उपलब्ध नहीं हुए। विद्यालयों के बन्द होने और पंचायतों के चुनाव होने के कारण विद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों से संपर्क नहीं हो पाया इसी कारण फील्ड इन्वेस्टीगटर्स को जनपदों में नहीं भेजा गया।

उत्तर प्रदेश में विकलांग समेकित शिक्षा के लिए वर्ष 1988-89 से 1990-91 के बीच जो धनराशि प्रदान की गयी थी उसका उपभोग

प्रमाण-पत्र उसी समय भारत सरकार को निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। वर्ष 1991 के बाद यह कार्यक्रम पूर्णतः स्थगित रहा और उस पर किसी तरह का कोई अनुदान भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।

जहाँ तक व्यय का प्रश्न है वहाँ अधिकांश जनपदों में कक्षा-कक्ष निर्माण प्रधान/उपकरण पर धनराशि व्यय की गयी क्योंकि कार्यक्रम का संचालन लगभग 9 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया। अतः कितने बच्चे लाभान्वित हुए उनका समाध्यात्मक विवरण निदेशालय में उपलब्ध न होने के कारण यहाँ उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है।

सम्प्रति विकलांग समेकित शिक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए एन.सी. ई.आर.टी. के निर्देशानुसार दो व्यक्तियों को निर्धारित मानदेय के आधार पर फील्ड इन्वेस्टीगेटर के रूप में रखा गया, जिन्होंने एन.सी.ई.आर.टी. में फरवरी में होने वाले प्रशिक्षण में प्रतिभाग लिया। फरवरी के बाद कुछ जिलों में लोकसभा में मध्यावधि चुनाव होने तथा बाद में पंचायत चुनाव घोषित हो जाने के कारण आँकड़ों का संकलन नहीं हो पाया और न ही अभिभावक तथा बच्चों का परिसंवाद एवं मूल्यांकन हो सका।

उल्लेखनीय है कि विकलांग समेकित शिक्षा के मूल्यांकन कार्यक्रम के चलते उत्तर प्रदेश के चार जनपदों में वृहद् कार्यक्रम के रूप में अंगीकृत करते हुए एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में यूनीसेफ सहायतित रुचि पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम से अच्छादित 17 जनपदों में समन्वयकों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गयी मार्गदर्शिका में विस्तार से विकलांग समेकित शिक्षा के संदर्भों को जोड़ा गया है।

इसी संदर्भ में यह भी सूच्य है कि समेकित शिक्षा की मूल अवधारणा एवं अध्यापकों के इन बच्चों के प्रति दायित्वों से सम्पूर्ण प्रदेश के 1.14 लाख प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3.10 लाख अध्यापकों को अभिप्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना प्रदेश के 13 मण्डलीय जनपदों तथा सुलतानपुर और बलिया सम्मिलित रूप से 15 जनपदों में स्थित प्राथमिक विद्यालय और 10 मण्डलीय जनपदों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1988 से 1991 तक संचालित रही।

10 जनपदों में एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना संचालित की गयी थी। शेष 5 जनपदों इलाहाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, और नैनीताल में केवल एक-एक प्राथमिक विद्यालयों में ही यह योजना संचालित रही इस प्रकार इस योजना में 15 प्राथमिक तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्र इस योजना से लाभान्वित हुए। (जनपदों की सूची संलग्न) है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना से आच्छादित विद्यालयों की सूची प्राथमिक स्तर :

1. प्राइमरी पाठशाला पूवी अहिरान, मेरठ।
2. प्राइमरी पाठशाला सरदार पटेल मार्ग, लाहामण्डी, आगरा।
3. प्राइमरी पाठशाला मूड़, बरेली।
4. प्राइमरी पाठशाला साउथी मलाका, इलाहाबाद।
5. प्राइमरी पाठशाला लहरतारा, प्रतापगढ़।
6. प्राइमरी पाठशाला चिनहट, लखनऊ।

7. राजकीय प्राइमरी पाठशाला, गोरखपुर।
8. प्राइमरी पाठशाला बेनाझासर, कानपुर नगर।
9. सरस्वती प्राइमरी पाठशाला, सिपरी बाजार, झांसी।
10. प्राइमरी पाठशाला बेनाझासर, कानपुर नगर।
11. प्राइमरी पाठशाला गांधी पार्क मुरादाबाद।
12. प्राइमरी पाठशाला राजपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल।
13. प्राइमरी पाठशाला नं. 5 पौड़ी गढ़वाल।
14. भृगु आश्रम प्राइमरी पाठशाला, बलिया।
15. राजकीय आदर्श विद्यालय, सुलतानपुर।

उच्च प्राथमिक स्तर

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेरठ।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय, आगरा।
3. उच्च प्राथमिक विद्यालय, बरेली।
4. उच्च प्राथमिक विद्यालय, बलिया।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालय, लखनऊ।
6. उच्च प्राथमिक विद्यालय, फैजाबाद।
7. उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोरखपुर।
8. उच्च प्राथमिक विद्यालय, झांसी।
9. उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुरादाबाद।
10. उच्च प्राथमिक विद्यालय, पौड़ी, गढ़वाल।

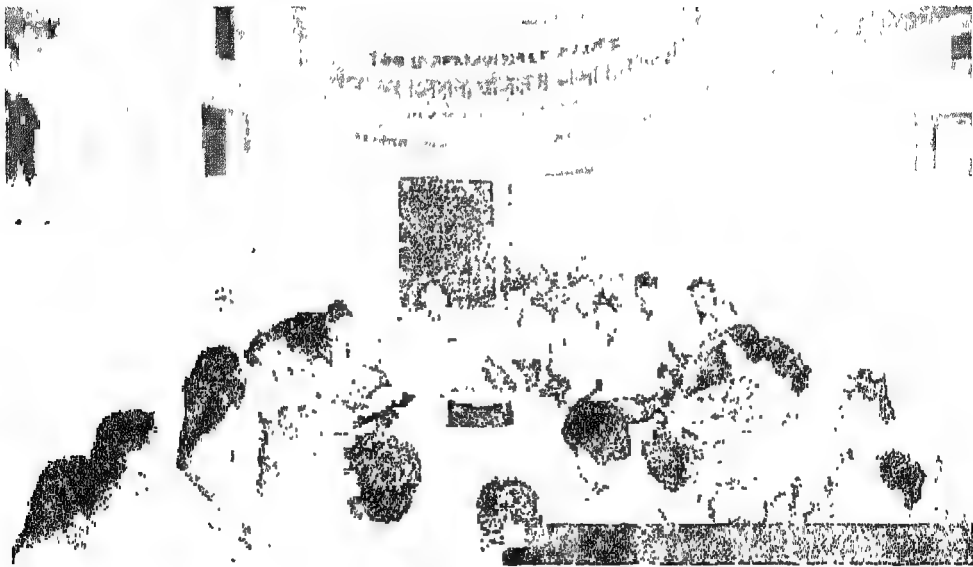
इस अवधि में फील्ड इन्वेस्टीगेटरों द्वारा जनपदों से जो सूचना प्राप्त हुई उसका विश्लेषण और आवंटित धनराशि के उपभोग की स्थिति जानने हेतु ऑकड़े विश्लेषित करने का कार्य किया गया। जिससे निम्न तथ्य उभर कर आये:

क्रम	जनपद का नाम	आवंटित धन	उपभोग की गयी धनराशि	अवशेष
1.	लखनऊ	1,81,950.00	1,06,000.00	75,950.00
2.	पौड़ी	1,46,550.00	शून्य	1,46,550.00
नोट: सम्पूर्ण धनराशि चालान द्वारा कोषागार में जमाकर दी गयी				
3.	नैनी	67,660.00	30,000.00	37,660.00
4.	गोरखपुर	60,363.00	60,363.00	शून्य
5.	कानपुर नगर	92,550.00	92,550.00	शून्य
6.	बलिया	85,640.00	65,453.00	20,187.00
नोट: जनपद से प्राप्त सूचना में अवशेष धनराशि का कोई विवरण या उल्लेख नहीं है।				
7.	बलिया जूनियर हाई स्कूल	1,05,000.00	1,05,000.00	शून्य

उक्त विवरण, जनपदों से प्राप्त सूचना, जो विद्यालयों से संकलित कर बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर भेज दी गयी है। जिसकी प्रमाणिकता निदेशालय से सूचना न प्राप्त होने के कारण पुष्ट नहीं हो पा रही है।

इसी अवधि में चार जनपदों में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना संचालित करने का प्रस्ताव और प्रशासनिक प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव भी बनाकर भारत सरकार को भेजा गया।

**INTEGRATED EDUCATION
FOR THE DISABLED
IN DPEP
(IED IN DPEP)
(U.P.)**



INTEGRATED EDUCATION FOR THE DISABLED (IED) IN DISTRICT PRIMARY EDUCATION PLAN (DPEP), (U.P.)

District Primary Education Plan (DPEP) is a Centrally Sponsored Scheme providing special thrust to achieve Universalization of Primary Education (UPE). The programme component include the construction of classrooms and new schools, opening of non-formal/alternative schooling centres, appointment of new teachers, setting up of block resource centres/cluster resource centres, teacher training, development of teaching learning material, research based interventions, special interventions for education of girls, SC/ST etc. The components of integrated education of children with disabilities and of distance education for improving teacher training have also been incorporated in the programme. The programme mainly aims at to provide access to primary education for all children, reducing drop out rates to less than 10%, increasing learning achievements of primary students by at least 25%, and reducing gap among gender and social groups to less than 5%.

The District Primary Education programme, Uttar Pradesh has included integrated education in the project to fulfill the educational needs of children with special needs. The ultimate goal of DPEP Uttar Pradesh is to achieve the goal of inclusive education. It has following objectives:

OBJECTIVES

1. To integrate children with mild and moderate disabilities to regular schools.
2. To ensure equal opportunities to children with disabilities from 6 to 11 years of age.
3. To create an enabling environment in the schools.
4. To provide parental guidance and to generate community support.
5. To support human resource activities and required personnels.
6. To set up resource centres at block and district levels.

COVERAGE

There is a total number of **645** blocks in **54** DPEP districts, out of which **224** blocks have been covered for integrated education for disabled in the year **2002-03**. Out of the total number of **77232** schools in **54** districts, **21045** schools have been covered under IED. There is a total number of **38449** children who have been identified as children with special needs, out of which **29089** have been sent to regular schools for integration. The children who require aids and appliances are **24764**, out of which **11652** have been provided the require aids and appliances through convergence. **167254** general teachers have been trained for integrated education for 8 days through mass training, and **25795** teachers who have been trained for 5 days.

Table No.1
DPEP in Uttar Pradesh at a glance

S.No.	Detailed Information Available		Covered under IED
1.	Total number of blocks in 54 DPEP districts	645	224
2.	Total number of schools in 54 districts	77232	21045
3.	Total number of children with special needs (6 to 14 years)	38449	29089
4.	Aids and appliances actually required	24764	11652
5.	General teachers trained through mass training (8 days training)	-----	167254
6.	Number of teachers trained for IED (5 days training programme)	-----	25795

As has been mentioned in table no.1 that **29089** children with special needs have been integrated in the selected blocks. There are **93414** children with special needs who have been integrated non-selected blocks in the primary schools. The detailed break up may be seen disabilities wise in the following table.

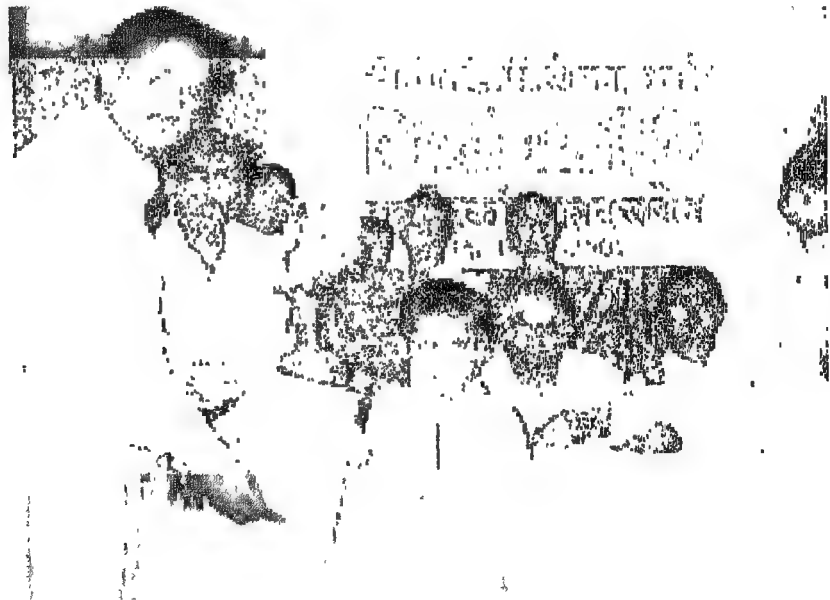
Table No.2

Children with different disability	Selected Block	Non-selected Blocks	Total
V1	2745	9200	11945
H1	3820	12775	16595
OH	17012	55752	72764
MR	3248	10206	13454
LD	2264	5481	7745
Total	29089	93414	122503

The above table shows that there are **11945** children who are with visual impairment, and **16595** are having hearing impairment. The maximum numbers of children are orthopedic handicap who are **72764** in numbers. **13454** children are having mental retardation and **7745** are having learning disability.

Assessment of children with disabilities

So far **283** medical assessment camps were organized and **28923** children with special needs have been assessed. These children were assessed by multi disciplinary team of specialist like ENT specialist, eye surgeon, orthopedic doctor etc. **9018** children were provided certificate by Chief Health and Medical Officer. In the following photograph the children with disabilities may be seen being provided with disability certificate.



Distribution of aids and appliances

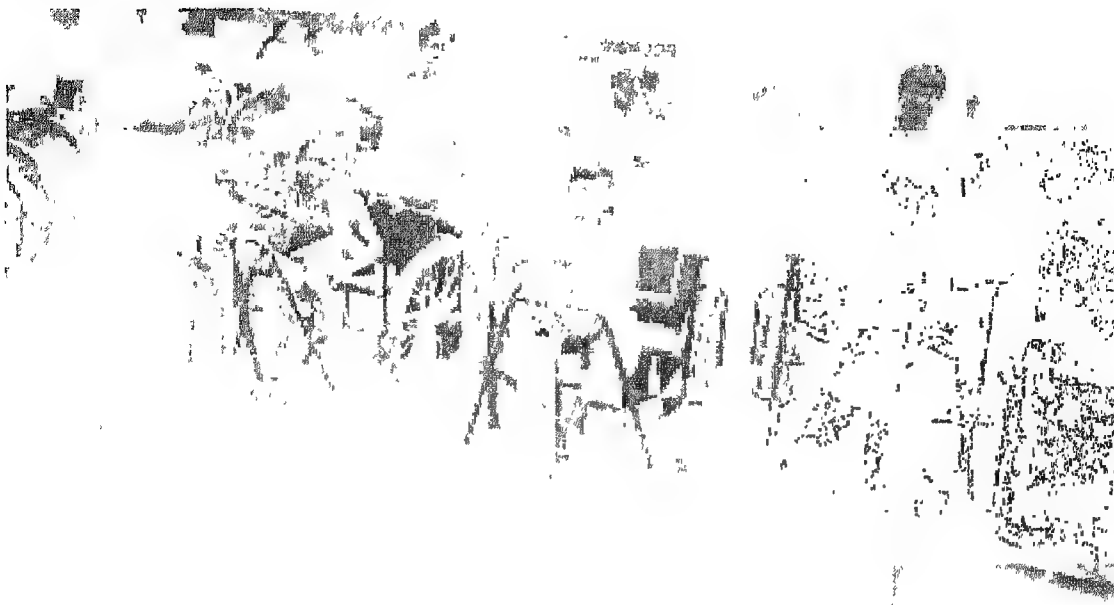
Aids and appliances were provided to children with special needs through convergence. Till now 11652 aids and appliances were provided to children with different disabilities. This can be seen in the following table.

Table No.3
Aids and appliances provided to children with special needs

1. Crutches	3532
2. Tricycles	2075
3. Wheel chairs	1030
4. Calipers	3121
5. Artificial limb	200
6. Walking sticks	25
7. Hearing aids	904
8. Blind sticks	356
9. Braille clock	158
10. Lowvision kit	60
11. Braille slate	191
Total	11652

In the following photographs children may be seen being provided with aids and appliances.





It may be highlighted here that some of the districts have taken exemplary initiatives. The District Magistrate Fatehpur's exemplary efforts have been appreciated by all. He has taken a lead by saturating on the demand of disabled persons for distributing aids and appliances in the district. A total of 4066 persons including 319 children of school going age group have been covered and a sum of rupees 82,59,700 worth of tricycles, crutches, wheel chairs and blind sticks were provided in well organized camps to 24066 persons in a short span of 6 months. Motivated from these efforts a few of the Gram Sabha contributed 3% of their allocated funds towards the common disability fund created at the district level.

Capacity Building and Manpower Development

A number of training programmes were conducted under capacity building and manpower development. 52 Districts Coordinators have undergone orientation programme for 5 days or 2 days in the area of integrated education. These programmes were organized by various institutes of rehabilitation council of India, MJP Ruhel Khand University, Bareilly, and SPO Lucknow. 166 teachers have been given a 45 days foundation course proposed by rehabilitation council of India. This was given by Uttar Pradesh institute for the hearing handicapped, Allahabad, Chetna Lucknow and IED Varanasi. 396 master trainers were trained for 10 days. This particular training programme was conducted by Amar Jyoti, New Delhi, Viklang Rural Research Society, Allahabad, MJP, Ruhel Khand University, Bareilly and different DIETs of Uttar Pradesh. 25795 primary teachers were given orientation for 5 days duration by master trainers, resource persons and district coordinators. 18 teachers have been trained for 1 month for brief course in mental retardation. This training programme was conducted by Amar Jyoti, Delhi. This may be viewed in the following table.

Table No. 4
Capacity Building and Manpower Development

S.No.	Category of personnels trained	No. of persons trained	Type of Training and Duration of Training course	Place of Training
1.	District Coordinators	52	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Days Orientation on IED • 2 Days orientation on IED 	<ul style="list-style-type: none"> • Various institutes of RCI • MJP R U Bareilly • SPO Lucknow
2.	Resource Persons	166	<ul style="list-style-type: none"> • 45 Days Foundation Course training in all disability 	<ul style="list-style-type: none"> • U.P. Institute for the Hearing handicapped Allahabad • Chetna, Lko • IID, Varanasi
3.	Master Trainers	396	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Days training on developed module 	<ul style="list-style-type: none"> • Amar Jyoti, New Delhi • V.K.R.R.S Alld. • MJP R U Bareilly • Different DIETs of U.P.
4.	P.S. Teachers of selected area	25795	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Days by MT/RP/DC 	<ul style="list-style-type: none"> • BRC/NPRC/DIET.
5.	Primary teaches	18	<ul style="list-style-type: none"> • One month Bridge course 	<ul style="list-style-type: none"> • Amar Jyoti, New Delhi.

Material development

A handbook was developed for general teacher covering all disabilities. It was prepared in Hindi. This is distributed among general teachers attending 5 days training programme. Besides this, folders for guidance for parents, teachers and community members on different disabilities have also been developed.

Initiatives taken by DPEP in U.P.

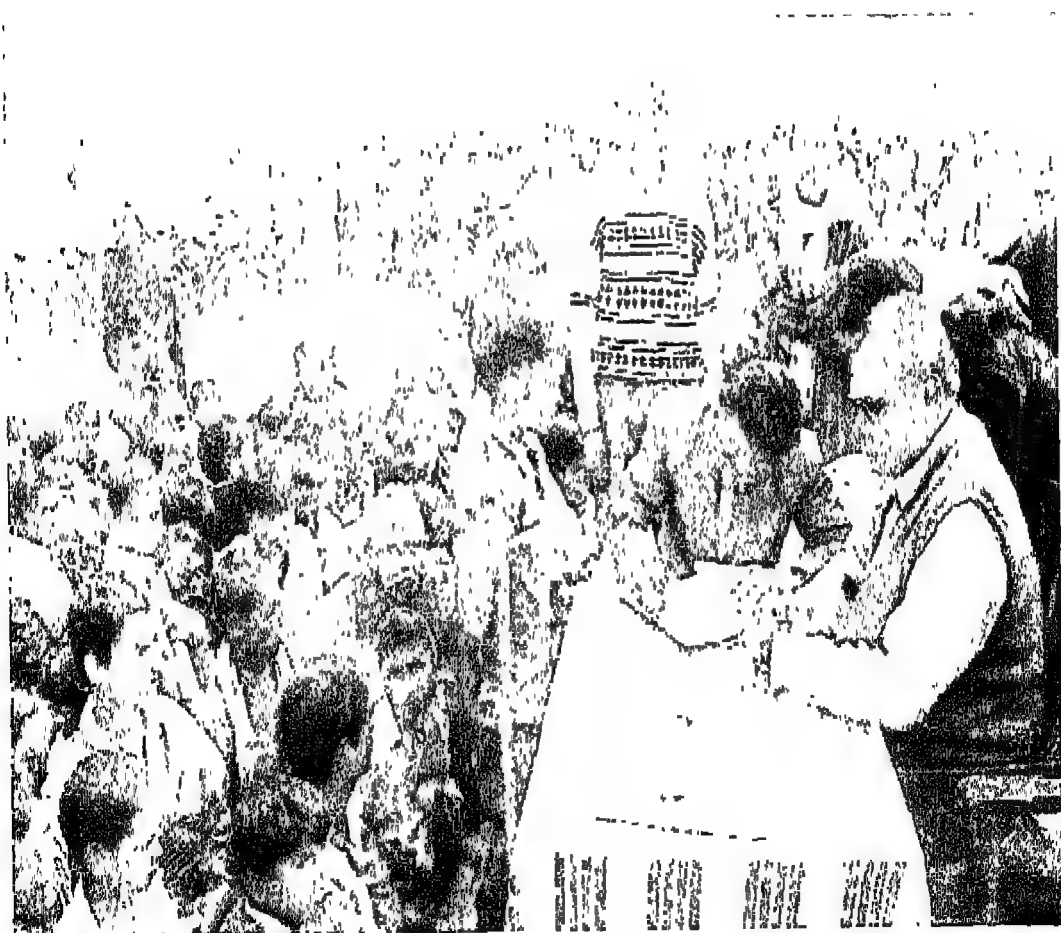
1. Village Education Committee (VEC) is the grass root level body, which plays a pivotal role in enlisting community participation for education and bringing the community and schools closer to establish an interactive and effective management. VEC is expected to give special attention to enroll the children with special needs and educate them.

There is provision of at least one guardian of disabled child in VEC. To sensitise VEC members along with community, IED component has been included in 3 days training module.

2. IED component has been included in Inservice Teacher Training module to make teachers sensitive towards the education of children with special needs.
3. A chapter 'Dosti' has been included in class III Environmental Studies (EVS) textbook to make children sensitive towards children with disability.
4. A chapter 'Aparajta' has been included in class VIII Hindi textbook to highlight that physical disability is not the hindrance in achievement of higher goals. Exercises have been framed to evoke an emotional bonding with people with disability.
5. All primary schools teachers concerning the blocks covered by IED undergo five days training to make them aware about the education of children with disabilities, & their identification, medical assessment, classroom management, parent counseling etc.

6. IED component has been incorporated in Basic Teachers' Training Programme.
7. There are some districts where there are no facilities of repairing of aids and appliances. So UP has planned to train at least one parent of disabled child from each block (who has knowledge of carpentry) for repairing & maintenance of aids and appliances. Duration of this training is three days & it will be conducted with the help of CRRC, Lucknow.
8. To give resource support a date is fixed for each BRC. This date is advertised properly. On this day Resource Persons, Master Trainers & District Coordinators collect at BRC. They counsel parents, assess children and give extra support such as special teaching, speech therapy & physiotherapy etc.
9. An integration camp for the parents of blind children has been organized in Basti district. In this camp parents learnt Braille. Now parents are helping to their children to write Braille.

आई.ई.डी.सी. जनशाला में (यू.पी.)



जनशाला भारत सरकार एवं यू.एन. एजेन्सीज के सहयोग से उ0प्रदेश के लखनऊ जनपद के 8 विकास खण्ड एवं नगर क्षेत्र के 17 शैक्षिक जोन में संचालित है । जनशाला सर्वशिक्षा अभियान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है । इस का न केवल सामान्य शिक्षा वरन विशेष बालकों की शिक्षा में भी अनूठा योगदान है । जनशाला निम्निलिखित उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ा ।

जनशाला कार्यक्रम के उद्देश्य

1. समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एम.टी.ए./पी.टी.ए. अभिभावक संघ का प्रशिक्षण
2. समुदाय के सहयोग से विद्यालय को सामुदायिक शालाओं के रूप में परिवर्तित करना ।
3. 6-11 बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, उपस्थिति तथा ठहराव हेतु विशेष प्रयास करना । (विद्यालय के सभी विकास कार्यक्रम तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली एजेंसियों के समन्वय से)
4. गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ।
5. रुचिपूर्ण, बालकेन्द्रित, लिंग समानता, बहुकक्षा शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ।
6. विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करना ।

जनशाला कार्यक्रम में 17941 विकलांग बच्चों की पहचान की गई । ये बच्चे विभिन्न विकलांगताओं से सम्बन्धित हैं । 17941 बच्चे लखनऊ के 10 अलग-अलग विकास खण्डों से निकाले गये। विभिन्न विकासखण्डों व विभिन्न विकलांगताओं के अनुसार इसका विवरण इस प्रकार है -

विकासखण्डवार विकलांगता विवरण जिला-लखनऊ

क्र सं	विभिन्न विकासखंड	अल्प दृष्टि	अन्धापन	मानसिक विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	योग
1.	बक्शी का तालाब	66	102	150	421	1014	1753
2.	चिन्हट	29	40	108	188	614	979
3.	गोसाईगंज	41	20	64	117	402	644
4.	हजरतगंज	2	19	24	17	63	125
5.	काकोरी	23	56	148	489	588	1304
6.	माल	20	103	190	755	1040	2108
7.	मलिहाबाद	48	58	181	722	822	1831
8.	होहनलालगं ज	14	29	68	133	312	556
9.	सरोजनीनगर	42	66	123	243	688	1162
10.	नगर क्षेत्र	582	278	968	1467	4184	7479
	योग	867	771	2024	4552	9727	17941

स्रोत- यू.एन.डी.पी.सर्वे

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 17941 में से सबसे अधिक बच्चे अस्थि विकलांगता वाले हैं, जो 9727 हैं। तत्पश्चात् श्रवण-विकलांग 4552, पुनः 2024 जो मानसिक रूप से विकलांग हैं। 867 बच्चे अल्पदृष्टि से ग्रसित हैं व 771 बच्चे अन्धेपन से पीड़ित हैं। यदि एक दृष्टि विभिन्न विकासखण्डों में पाये जाने वाले विकलांग

बच्चों पर डालें तो ज्ञात होगा कि सबसे अधिक विकलांग बच्चे नगर क्षेत्र में हैं जो 7479 हैं । इसके पश्चात् आता है माल जहाँ 2108 बच्चे पाये गये और पुनः 1753 बच्चे जो बक्शी का तालाब में पाये गये ।

जनशाला द्वारा विकलांग बालकों के लिये विभिन्न प्रकार के प्रयास किये गये । जिसमें एक दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक, विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिभावक प्रशिक्षण, महिला प्रेरक समूह प्रशिक्षण, विकलांग बच्चों का सर्वे, ब्लाक समन्वयकों, न्याय पंचायत समन्वयकों तथा ग्राम पुर्नवास कर्मियों का प्रशिक्षण सम्मिलित है ।

विकलांग बच्चों हेतु किए गए प्रयास

- दिनांक 9.11.2001 को उच्च स्तरीय बैठक राज्य परियोजना कार्यालय में ।
- अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन सेन्टर दिल्ली से 15 अध्यापकों का मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण ।
- दो दिन विकलांग बच्चों की शिक्षा (समेकित शिक्षा) पर चर्चा (विकलांग कल्याण विभाग) के विशेषज्ञों द्वारा- दस दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण ।
- ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण में एक दिन-विकलांग बच्चों की शिक्षा सहयोग पर चर्चा।
- माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ/महिला प्रेरक समूह के प्रशिक्षण में आधा सत्र विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं सहयोग पर चर्चा ।

- समेकित शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए छः फोल्डर का वितरण ।
- प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को विभिन्न एन.जी.ओ. द्वारा परीक्षण एवं उपकरण वितरण ।
- जनशाला के सहयोग से नगर क्षेत्र में 0-18 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का सर्वे ।
- 0-18 वय वर्ग के सभी बच्चों का परीक्षण एवं उपकरण वितरण ।
- ब्लाक समन्वयकों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों का ग्राम पुनर्वास कर्मियों के साथ प्रशिक्षण/विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से ।

विभिन्न विभागों व संस्थाओं से तालमेल बनाकर आगे बढ़ना सफलता की एक अचूक कुंजी है । यूनीसेफ के सहयोग से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा चलाये गये “ प्रोजेक्ट इन्टीग्रेटिड एजुकेशन फार डिसएबल्ड “ की सफलता का एक राज यह भी था कि उसमें विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रालयों व विभिन्न संस्थाओं से तालमेल बनाया गया था । इस तालमेल से सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला । जनशाला ने भी ऐसा ही किया । जनशाला ने स्वयं सेवी संस्थाओं, विकलांग कल्याण विभाग, यू.एन.डी.पी. तथा क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र के साथ एक अनूठा समन्वय स्थापित कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है ।

विभिन्न विभागों/संस्थाओं से समन्वय

- स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ
- विकलांग कल्याण विभाग के साथ ।

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की योजना के साथ ।
- क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र के साथ ।
- चेतना संस्थान लखनऊ के साथ ।

जनशाला ने निम्नलिखित क्रियाकलापों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है ।

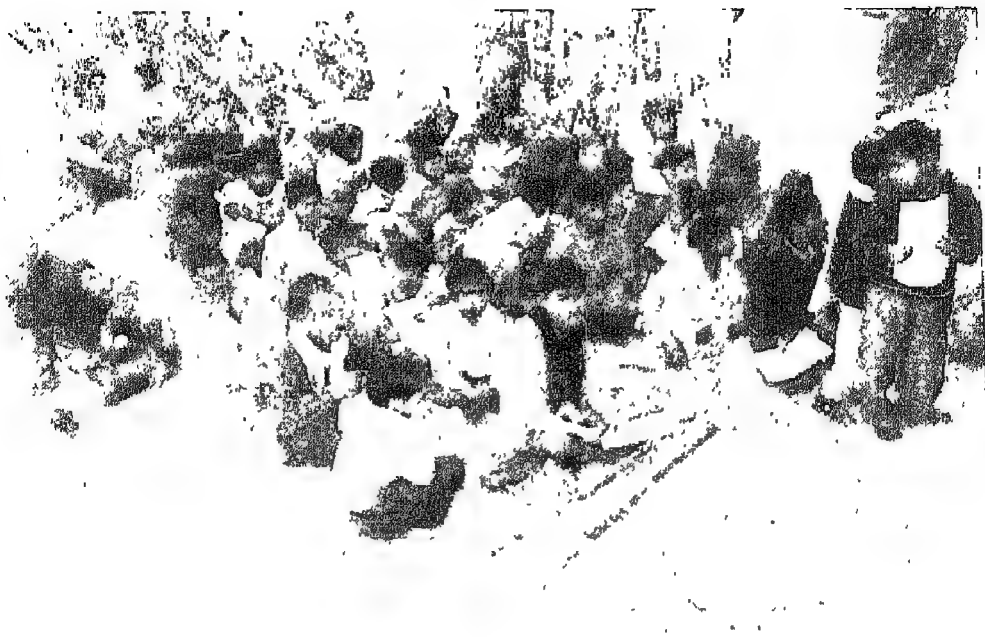
विकलांग बालकों से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन

- क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र के साथ मिलकर स्थान एवं तिथि का चुनाव ।
- शिविर के स्थान को बाधा रहित बनाना ।
- सभी शिक्षकों एवं विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार ।
- अनुमानित संख्या के आधार पर क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र द्वारा वितरण उपकरणों की व्यवस्था ।
- क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र के सहयोग से योग्य डाक्टरों द्वारा परीक्षण एवं उपकरण वितरण ।
- कैंम्पों के दौरान जन सहयोग से विकलांग बच्चों हेतु अल्पाहार की व्यवस्था ।
- कुछ बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए संदर्भित (रैफर) किया जाना।

15 वर्ष से अधिक के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की जानकारी उपलब्ध कराना ।

जनशाला द्वारा आयोजित विभिन्न क्रियाकलाप





ANNEXURE

QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS TO STUDY THE IMPACT OF INTEGRATED EDUCATION FOR DISABLED CHILDREN (IEDC)

Janak Verma
Debendra Nath Dash



DEPARTMENT OF EDUCATION OF GROUPS WITH SPECIAL NEEDS
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS TO STUDY THE IMPACT OF INTEGRATED EDUCATION FOR DISABLED CHILDREN (IEDC)

1. State/UT _____

2. District _____

3. Block/Tehsil _____

4. City/Village/Town _____

Name of the School _____

Postal Address _____

Name and Designation of the Teacher

Qualification

(Write the highest qualification, give No. in the box)

(a) Academic:

- 10 +2 or equivalent (1)
- graduate or equivalent (2)
- Post graduate (3)
- M.Phil. (4)
- Ph.D (5)
- Any other (6)

(b) Professional:

- C.T./LT/BT/B.Ed or equivalent (1)
- M.Ed. (2)

(c) Professional qualification in Special Education:

(i) Diploma in Special Edu.:

VH (1)

S&HI (2)

MR (3)

OH (4)

LD (5)

Multiple (6)

(ii) B.Ed. in Special Edu. (1)

M.Ed. in Special Edu (2)

(d) Professional Training in Special Education:

1 week training (1)

2 weeks training (2)

6 weeks training (3)

3 months training (4)

6 months training (5)

1 year multi-category training (6)

1 year single disability training (7)

Degree course in single Disability (8)

(please specify)

(e) Working as a:

Headmaster/Headmistress (1)

General Teacher (2)

Resource Teacher (Multicategory) (3)

Resource Teacher (Single Disability) (4)

1. Area in which School is located:

Rural (1)

Urban (2)

☐

2. Management of School:

Government (1)

Local Body (2)

Private aided (3)

Private unaided (4)

☐

3. If Government, the school is managed by:

State Government (1)

Central Government (2)

☐

4. Type of school:

Boys (1)

Girls (2)

Co-educational (3)

☐

5. Classes Taught:

From class _____ to class _____

6. Medium of Instruction _____

7. Are you familiar with the concept of

Integrated Education for Disabled Children?

Yes (1)

No (2)

☐

8. No. of Integrated School in village/city/town _____

9. No. of special School in your village/city/town _____

10. Since when are you working in this school _____

11. Since when IEDC Scheme was implemented in your School _____

12. No. of Trained Teachers in special education in your school.

Name of Teacher	Type of Training	Duration of Training	Place of Training

13. As a resource teacher, are you getting additional salary?

Yes (1)

No (2)

14. Is the additional salary received in time?

Yes (1)

No (2)

15. What is the pupil teacher ratio for children with special needs in your school ? _____

16. Does your school have a resource centre ?

Yes (1)

No (2)

17. Who is looking after the resource centre? _____

18. How many schools are covered by this resource centre ? _____

19. Enlist children attending the resource centre in the session 1998-99.

S.No	Name of School	No. of children covered												Total
		VH		S&HI		MR		OH		LD		MH		
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B

VH = Visually Handicapped
 S&HI = Speech and Hearing Impairment
 MR = Mentally Retarded
 OH = Orthopaedically Handicapped
 LD = Learning Disabled
 MH = Multiple Handicapped
 B = Boys
 G = Girls

20. How many times in a month the children avail the resource centre facilities.

Once (1)
 Twice (2)
 Thrice (3)
 Four times (4)

21. Give suggestions for the improvement of resource centre.

22. In the absence of resource centre how do you manage the children with special needs?

23. Enlist the number of non-disabled children in your school in the block years mentioned in the table?

Years	No. of Non-disabled Children		
	Boys	Girls	Total
1975-79			
1980-84			
1985-89			
1990-94			
1995-99			
Total			

24. Enlist the total number of disabled children identified and assessed in your school since IEDC scheme is implementing. (Please ensure children identified in the previous years should not be added in the next year.)

[illegible]

5. Enlist the children with special need identified in your school during the academic year 1998-99.

[illegible]

26. Enlist children with special need assessed in your school during the academic year 1998-99.

[illegible]

27. Enlist the total number of out-of-school children with special need identified and assessed by your school since IEDC scheme is implementing. (Please ensure children identified in the previous years should not be added in the next year)

[illegible]

28. Enlist the out-of-school children with special need identified in your school during the academic year 1998-99.

[illegible]

29. Enlist the out-of-school children with special need assessed in your school during the academic year 1998-99.

[illegible]

30. Enlist the total number of disabled children sent for integration directly in your school during the period 1994-99. (Please ensure children sent for integration directly in your school in the previous years should not be added in the next year)

[illegible]

31. Enlist the total number of disabled children referred to the resource teacher for preparation for integration directly in your school during the period 1994-99 (*Please ensure children referred to resource teachers in the previous years should not be added in the next year.*)

[illegible]

32. Enlist the number of children prepared in different skills.

[illegible]

33 What instructional materials have been procured/developed for children with special need?

Children with special need	Material procured	Material developed
VH		
S&HI		
MR		
OH		
LD		
MH		

34. Do you think that these instructional materials are useful even for the other children?

Yes (1)

No (2)

35. Do you think that integrated education has helped the children with special need to attend regular school?

Yes (1)

No (2)

36. Do you think that integrated education has improved the attendance of the children with special need in the school?

Yes (1)

No (2)

37. Do you think that due to the introduction of integrated education programme the children with special need are able to progress?

Yes (1)

No (2)

- | | | | |
|--|---------|--------|----------------------|
| 38. Whether integrated education has helped the children with special need to participate in different curricular activities of the school ? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 39. Whether integrated education has helped the children with special need to participate in co-curricular activities as per their capabilities? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 40. Whether the general teachers borrow teaching aids from resource centre to use in the classroom? | Yes (1) | No (1) | <input type="text"/> |
| 41. Whether integrated education has helped general teachers in developing positive attitude towards children with special need ? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 42. Whether integrated education has helped other children in developing positive attitude towards children with special need ? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 43. Whether integrated education has helped children with special need to improve their personal/social skills? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 44. Whether integrated education has helped children with special need to improve their academic skills? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 45. Whether presence of children with special need has made the general teacher a better teacher? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 46. Whether integrated education has improved the self-esteem of children with special need? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 47. Do you think that integrated education has reduced the drop-out rate of children with special need and other children? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 48. Do you think that integrated education has helped the other children to improve their academic as well as non-academic skills? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |
| 49. Do you think that integrated education will help in achieving the targets of Education For All in the country? | Yes (1) | No (2) | <input type="text"/> |